'डबल इंजन' की रफ्तार ने बदली उत्तर प्रदेश की आर्थिक तस्वीर

अजय जायसवाल • जागरण

- बीमारू राज्य से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की कुंजी राजनीतिक स्थिरता और वित्तीय अनुशासन
- तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश को देश में सबसे आगे निकलने को अभी उठाने होंगे कई और कदम

लखनऊ: देश में सर्वाधिक 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश पिछले सात वर्षों में बीमारू राज्य की छवि से उबरकर 'आत्मनिर्भर' बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपी की बदलती तस्वीर का अगर कोई बड़ा कारण है तो वह राजनीतिक स्थिरता के साथ ही 'डबल इंजन' सरकार का दम। दावा तो यह है कि आगे भी यही स्थिति बनी रही तो आर्थिक मोर्चे पर देश में अग्रणी महाराष्ट्र व गुजरात जैसे राज्यों को भी उत्तर प्रदेश पछाड़ देगा लेकिन हकीकत में सबसे आगे निकलने के लिए योगी सरकार को अभी और भी तमाम कदम उठाने होंगे। दशकों से पिछड़ेपन का शिकार रहे पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र पर सरकार को और फोकस बढ़ाना होगा। दक्षिण के राज्यों की तरह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) को बढ़ाने के लिए नीतियों को और लचीला बनाने के साथ ही राज्य की बेहतर होती तस्वीर को भी खूब उभारना होगा।

पूर्व में राजनीतिक अस्थिरता के चलते उत्तर प्रदेश, देश के दूसरे कई छोटे राज्यों से भी लगातार पिछड़ता रहा। गठबंधन की सरकारों में कुप्रबंधन से राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होती गई। ऐसा समय भी आया जब घपले-घोटाले, भ्रष्टाचार, खराब कानून-व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं के अभाव से उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश से मुंह ही मोड़ लिया जिससे प्रदेश की छवि बीमारू राज्य वाली बनती गई। वर्ष 2014 में केंद्र में मोदी सरकार और फिर वर्ष 2017 में प्रचंड बहुमत से राज्य में योगी सरकार के बनने के बाद समग्र और संतुलित विकास से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलना शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्य-नाथ द्वारा खासतौर से सूबे की कानून-व्यवस्था सुधारने के साथ ही वित्तीय अनुशासन और बेहतर प्रबंधन से राज्य में निजी निवेश बढ़ने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदलने लगी। सात वर्षों में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) जहां लगभग दोगुणा हो गया, वहीं बेरोजगारी दर दो-तिहाई घट गई। प्रदेशवासियों पर कर का बोझ बढ़ाए बिना केंद्रीय करों की औसत वृद्धि दर से कहीं ज्यादा अब राज्य सरकार के खुद के राजस्व कर की दर है। राज्य पर कर्ज का बढ़ता बोझ जरूर चिंता बढ़ाने वाला है लेकिन सरकार बढ़ती कमाई से विकास मद में दूसरे अग्रणी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक धन खर्च कर रही है।

माना जाता है कि मोदी-योगी की 'डबल इंजन' सरकार के दम से आर्थिक मोर्चे पर भी प्रदेश की बेहतर होती तस्वीर को देखते हुए ही प्रदेशवासियों ने विपक्ष को सत्ता से दूर रखा। ढाई वर्ष पहले फिर बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने के बाद योगी प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। चूंकि मोदी सरकार हैट ट्रिक लगाने में कामयाब रही है, इसलिए राज्य को 'डबल इंजन' सरकार से मिलने वाले फायदे बरकरार हैं। भविष्य में भी विपक्षी, सत्ता के करीब न पहुंच पाएं, इसके लिए मोदी-योगी सरकार प्रदेश को हर मोर्चे पर आगे ले जाने में जुटी हुई दिखाई देती है। आर्थिक स्थिति को लेकर दो दिनों में प्रकाशित आलेखों से साफ है कि वर्ष 2017 में सपा के सत्ता से बाहर होने के बाद योगी सरकार के अब तक के कार्यकाल में राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आने के साथ ही राजकोषीय घाटा कम हुआ है और प्रतिव्यक्ति आय में लगभग दोगुणा का इजाफा हुआ है। एफडीआइ भी चार गुणा से ज्यादा बढ़कर 12,615 करोड़ रुपये पहुंचा है लेकिन अग्रणी राज्यों से आगे निकलने के लिए राज्य में विदेश निवेश को बढ़ाने पर अभी सरकार को बहुत ध्यान देना होगा।

जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार के तमाम प्रयासों से स्वयं के कर राजस्व की औसत वृद्धि दर बढ़कर 12.92 प्रतिशत पहुंच चुकी है, वहीं केंद्रीय करों की प्राप्ति की औसत दर 10.68 प्रतिशत है। वैसे आंकड़ों के दम पर दावा है कि जिस रफ्तार से आर्थिक मोर्चे पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है उससे भविष्य में महाराष्ट्र, गुजरात सहित दक्षिण भारत के अग्रणी राज्यों से भी यूपी आगे होगा। हालांकि, अभी प्रदेश की सुधरती जीएसडीपी में गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज और मेरठ जैसे जिलों की ही अहम भूमिका है जबकि अग्रणी राज्यों से आगे निकलने के लिए सरकार को तेजी से ऐसे और कदम भी उठाने होंगे कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र के पिछड़े जिले भी जीएसडीपी में योगदान बढ़ा सकें। गौर करने की बात यह भी है कि सात वर्षों में राज्य पर कर्ज का बोझ 3.4 प्रतिशत बढ़कर जीएसडीपी का लगभग एक तिहाई 32.7 प्रतिशत पहुंच गया है जिसे कम करने के भी उपाय सरकार को करने होंगे।

खजाने की कीमत पर...

12,615 करोड़ हुआ एफडीआइ

विकास मद में बढ़ता व्यय (करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	कुल धनराशि
2017-18	1,85,197.96
2022-23	3,05,869.06
2023-24	4,21,345.06
2024-25	4,41,512.87

नोट- वर्ष 2023-24 व 2024-25 में व्यय अनुमानित है।

अग्रणी राज्यों को भी पीछे छोड़ेगा उप्र वित्त मंत्री

सुरेश कुमार खन्ना

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना दावा करते हैं कि 'डबल इंजन' की स्थिर सरकार बने रहने पर उत्तर प्रदेश भविष्य में आर्थिक मोर्चे पर अग्रणी राज्यों को भी पीछे छोड़ देगा। अपने दावे को वह तर्क का आधार भी देते हैं कि हमने फिजूलखर्ची पर कड़ाई से अंकुश लगाया तो वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखा है। पूर्व की अखिलेश सरकार में जहां एफआरबीएम (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन) कानून के तय मानकों का पालन नहीं किया गया वहीं हमने चालू वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के तय मानक 3.5 प्रतिशत से कम 3.46 प्रतिशत रखने की प्रतिबद्धता जताई है। हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

राज्य का बढ़ता अपना कर राजस्व (करोड़ रुपये)

वित्तीय वर्ष	धनराशि
2016-17	85,966.25
2017-18	97,393.00
2018-19	1,20,122.85
2019-20	1,22,825.83
2020-21	1,19,897.30
2021-22	1,47,367.74
2022-23	1,74,087
2023-24	2,12,731
2024-25	2,70,086

सात वर्षों में यूपी की बदलती तस्वीर को बयां करते आंकड़े

विषय	वर्ष-2016-17	वर्ष-2024-25
कुल आकार	3.46 लाख करोड़	7.36 लाख करोड़
जीएसडीपी	12.75 लाख करोड़	24.99 लाख करोड़
प्रति व्यक्ति आय	47,118 रुपये	83,636 रुपये
सीडी रेशियो	46 प्रतिशत	60 प्रतिशत
बैंकिंग व्यवसाय	12.75 लाख करोड़	26 लाख करोड़
प्रा.सेक्टर में बैंक लोन	4.55 लाख करोड़	15.5 लाख करोड़
निर्यात	89 हजार करोड़	दो लाख करोड़
बेरोजगारी दर	6.2 प्रतिशत	2.4 प्रतिशत
महिला श्रम बल	13.5 प्रतिशत	31.2 प्रतिशत
राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का)	4.39 प्रतिशत	3.46 प्रतिशत
राजस्व प्राप्तियां	2,56,875 करोड़	7,21,133.82 करोड़
राज्य का कर राजस्व	86 हजार करोड़	2,70,086 करोड़
सेल्स टैक्स व वैट	51,883 करोड़	1,56,981.89 करोड़